संपादकीय जागरण

शनिवार, 3 नवंबर, 2018 : कार्तिक कृष्ण 11 वि. 2075

मूर्ख की तरह बोलने के बजाय चुप रहना अच्छा है

प्रतीक्षा ही उचित है

इसमें दोराय नहीं कि अयोध्या विवाद के समाधान में देरी हो रही है और हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी तक टालकर शीघ्र फैसले की उम्मीदों पर पानी भी फेर दिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मंदिर निर्माण के प्रबल आकांक्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए। संघ के सर कार्यवाह भैय्या जी जोशी की ओर से जिस तरह यह कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो 1992 की तरह का आंदोलन फिर से चलाया जाएगा उससे तो यही ध्वनित होता है कि सरकार से ऐसे समय हस्तक्षेप चाहा जा रहा है जब उसके लिए ऐसा करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। पहला सवाल तो यही उठेगा कि आखिर चार साल तक इस मामले की सुध क्यों नहीं ली गई और वह भी तब जब अयोध्या में मंदिर निर्माण भाजपा के एजेंडे में था? आम चुनाव के ठीक पहले किसी तरह की कानूनी पहल की व्याख्या इस रूप में भी होगी कि महज चुनावी लाभ लेने की दृष्टि से ऐसा किया जा रहा है। यह बात और है कि ऐसी व्याख्या करने में माहिर विपक्षी दल तब भी भाजपा पर तंज कसते हैं जब वह राम मंदिर निर्माण की बात नहीं करती। अयोध्या में मंदिर निर्माण के आकांक्षी यह भी ध्यान रखें कि परिपाटी यही है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हो उस पर कानून बनाने अथवा अध्यादेश लाने से बचा जाता है। जो लोग राम मंदिर निर्माण के लिए कानून का सहारा लेने की मांग कर रहे है उन्हें इससे भी अवगत होना चाहिए कि अगर कानून का सहारा लिया जाता है तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

हालांकि संघ ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जरूरत पड़ने पर आंदोलन छेड़ने से उसका आशय क्या है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आज केंद्र के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें हैं। क्या यह आंदोलन इन्हीं सरकारों पर दबाव बनाने के लिए होगा? सवाल यह भी है कि जब देश आम चुनाव के मुहाने पर है तब राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन छेड़ना कितना उचित होगा? निःसंदेह ऐसे सवालों के बीच यह सवाल भी अपनी जगह है कि आखिर अयोध्या मामला सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता में क्यों नहीं है? इस मसले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आए आठ साल बीत गए और फिर भी इसका अता-पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कब करेगा? निःसंदेह ऐसे तर्कों के लिए कोई बहुत अधिक गुंजाइश नहीं है कि चुनाव के वक्त अयोध्या मामले पर फैसला देना सही नहीं होगा, क्योंकि अदालतें यह नहीं देखतीं कि उनके फैसलों के वक्त कहीं चुनाव हो रहे हैं या नहीं? अयोध्या मामले में फैसला सुनाने में जरूरत से ज्यादा देरी के बावजूद उचित यही है कि जब इतनी प्रतीक्षा की गई है तब फिर कुछ दिन और इंतजार किया जाए। केवल इंतजार ही नहीं किया जाए, बल्कि सभी की ओर से यह कोशिश भी की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैसे सद्भाव के माहौल में अमल किया जाए?

अयोध्या का दीपोत्सव

पिछले बरस राम नगरी अयोध्या 'त्रेता युग' जैसी दिवाली की गवाह बनी थी। अयोध्या का दीपोत्सव एक बार फिर इतिहास बनाने जा रहा है। इस बार न केवल दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला मुख्य अतिथि होंगी, बल्कि इंडोनेशिया, श्रीलंका, रूस, त्रिनिदाद, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया, लाओस व रूस सहित कुल सात देशों के 125 कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से भारत संग सांस्कृतिक रिश्तों की जड़ें मजबूत बनाएंगे। आज दुनिया विभिन्न आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक कारणों से तमाम अलग-अलग गुटों में बंटी है। ऐसे में देश का केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में दुनिया के लगभग हर हिस्से में भारत की साख और संबंधों को मजबूती देने में लगा हुआ है। इन प्रयासों को और ऊंचाई देने की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तरीके से की है।

> यह दुनिया भर में बसे भारतीयों को उनकी जड़ों से जोड़ने और उन्हें गौरव दिलाने का भी एक सशक्त माध्यम है

वस्तुतः इस दिशा में व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध और सांस्कृतिक गतिविधियां सबसे अच्छा और कारगर माध्यम साबित होंगी। इसी के तहत अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां न केवल विभिन्न देशों के कलाकार एक दूसरे की संस्कृति से न केवल परिचित होंगे, बल्कि मिसाल भी कायम करेंगे। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ने संस्कृति के पुनरुद्धार और उसे नई प्रतिष्ठा व ऊंचाई देने का जो प्रयास विभिन्न माध्यमों से शुरू किया है, वह रंग लाने लगा है। चाहे वह बरसाने की होली हो या अयोध्या की दिवाली। यह दुनिया भर में बसे भारतीयों को उनकी जड़ों से जोड़ने और उन्हें गौरव दिलाने का भी एक सशक्त माध्यम है। भारत से जुड़कर वे इसकी प्रगति में हिस्सेदार ही बनेंगे। कुल मिलाकर इस दीपोत्सव का चौतरफा सकारात्मक संदेश जाता दिख रहा है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में तेज सुधार मोदी सरकार के प्रयासों का नतीजा है?

आज का सवाल
क्या आगामी आम चुनावों में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बन सकता है?

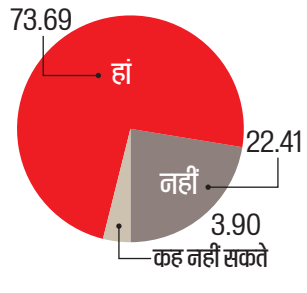

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y – हां, **N** – नहीं, **C** – कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

कुपोषण के खिलाफ कारगर उपाय

अभिनव प्रकाश

पोषण के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना अमल में लाने का मतलब आइसीडीएस या आंगनबाड़ी केंद्रों को खत्म करना नहीं, परंतु उन पर व्यर्थ का बोझ कम करना है

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4) के सर्वे अनुसार भारत में हर तीसरा बच्चा कुपोषित है। देश में 35.7 प्रतिशत बच्चे कम-वजनी हैं, 38.4 प्रतिशत अविकसित हैं और हर दूसरा बच्चा खून की कमी से ग्रस्त है। 15 से 49 वर्ष की आयु की 53 प्रतिशत महिलाएं रक्त अल्पता से पीड़ित हैं। ये आंकड़े भारत में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की भयावह स्थिति को रेखांकित करते हैं। मां का कुपोषण स्वतः ही बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि वर्तमान नीतियां कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रही हैं। दरअसल कुपोषण के खिलाफ वर्तमान प्रयास विभिन्न सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं जिनमें मध्यांतर आहार योजना यानी मिड डे मील और एकीकृत बाल विकास सेवाएं यानी आइसीडीएस मुख्य हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए बनी आइसीडीएस की हालत पर आज कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कुपोषण आजीवन असर दिखाता है। देखा जाए तो आइसीडीएस के केंद्र में आंगनबाड़ी केंद्र हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र आज भी वांछित नतीजे देने में असफल प्रतीत हो रहे हैं। इसका कारण दोषपूर्ण नीति निर्धारण और भ्रष्टाचार है जिससे लाभार्थी को सही सुविधा नहीं मिल पाती है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में आइसीडीएस की कमियों को उजागर किया है जैसे कि बजट को अन्य मदों में खर्च करना, वेतन के भुगतान के लिए अवास्तविक बजट, व्यय का गलत विवरण, खराब रिकॉर्ड रखरखाव इत्यादि प्रमुख हैं। इसी प्रकार आइसीडीएस के प्रभाव अध्ययन और बच्चों के पोषण की स्थिति पर कार्यक्रम मूल्यांकन रिपोर्ट 2015 के अनुसार 22.5 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्धारित दवाई नहीं हैं, 41 प्रतिशत में जगह का अभाव है और केवल 48.2 प्रतिशत में सफाई और स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखा जाता है। यह स्थिति आइसीडीएस को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने के लिए उसके पुनर्गठन की तत्काल आवश्यकता की ओर इंगित करती है।

वर्तमान में आइसीडीएस के पास कई लक्ष्य हैं जैसे बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखने के लिए विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन में प्रभावी समन्वय को स्थापित करना, बच्चों के स्कूल छोड़ने के सिलसिले को थामना। मां को सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को सही तरीके से पूरा करने के लिए प्रशिक्षित करना भी इसके कार्यों में शामिल है। इसके लिए आइसीडीएस आंगनबाड़ी केंद्र पूरक पोषण, प्री-स्कूल गैर-औपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच-पड़ताल और रेफरल सेवाएं प्रदान करता है। यह स्पष्ट है कि हम एक ही नीति से बहुत से उद्देश्यों को लक्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके चलते किसी भी उद्देश्य में वांछित सफलता नहीं मिल पा रही है। इसका सबसे अधिक प्रभाव पीड़ित गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं पर पड़ता है। इससे सेवा वितरण मॉडल के प्रभावी होने पर गंभीर प्रश्न उठता है?

अवधेश राजपूत

इसीलिए नीति आयोग की 'भारत राष्ट्रीय पोषण रणनीति' ने आइसीडीएस में सुधार की वकालत की है। इस रणनीति में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण उपलब्ध करने के बजाय महिलाओं को सीधे बैंक खातों में रुपये देने की बात कही गई है। उज्ज्वला रसोई गैस सिलेंडर और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण मॉडल की सफलता के बाद इसे आइसीडीएस में लागू करना एक बड़ा कदम होगा। कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी और परिवार की आय में कमी होना है जबकि आइसीडीएस घरेलू खाद्य सुरक्षा को संबोधित नहीं करता। इसलिए किसी भी समग्र समाधान में आय की भरपाई करने का दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। इसके लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण यानी डीबीटी सबसे अच्छा उपलब्ध विकल्प है। दूसरा कारण, घर में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कमजोर होना है। ऐसे में उन्हीं के जन-धन खाते में सरकार की तरफ से सीधा पैसा आने से उनकी स्थिति मजबूत होगी और उन्हें अपने और बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य के लिए फैसला लेने में आजादी होगी। घर और समाज में मां की स्थिति मजबूत होने से आने वाली पीढ़ी के पोषण, स्वास्थ्य, और शिक्षा पर अपने-आप ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा कारण, महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले आहार पर निर्भर रहना पड़ता है जो कई बार उनके स्वाद के अनुकूल नहीं होने के साथ-साथ हर इलाके में एक समान होता है। डीबीटी से महिलाओं को अपना आहार चुनने की आजादी मिलेगी और वे स्थानीय भौगोलिक, जलवायु और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपना आहार और पोषण चुन सकेंगी।

इसका सीधा असर उनके स्वस्थ पर पड़ेगा। अभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकारी प्रावधान के तहत स्थानीय जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता है। डीबीटी आंगनबाड़ी केंद्रों में आहार देने में होने वाले जातिगत भेदभाव के समाधान में भी सहायक होगा। शोध के मुताबिक आइसीडीएस में व्याप्त जातिगत भेदभाव दलित और अन्य पिछड़ी जाति के बच्चों के कुपोषण में कम सुधार के लिए जिम्मेदार है। डीबीटी बांग्लादेश, दक्षिण अमेरिकी देशों में अपनी सार्थकता सिद्ध कर चुका है। वर्तमान में भारत में पुदुचेरी में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए कुलविलाक्कु एवं अरवनिपु योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना में प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण का सकारात्मक परिणाम सामने है।

प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के विरुद्ध पहले जो दलीलें दी जाती थीं वे आज खरी नहीं उतरतीं। आज भारत में 77 प्रतिशत महिलाओं के पास बैंक खाते हैं। राजस्थान जैसे प्रांत में जहां आइसीडीएस का कवरेज मात्र 34 प्रतिशत है, प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण तत्काल ही आहार और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के विरुद्ध अन्य तर्क दरअसल नीति निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित हैं, जो आज आधार, डिजिटल टेक्नोलॉजी इत्यादि के माध्यम से आसानी से हल किए जा सकते हैं। यहां पर यह कहना भी आवश्यक है कि पोषण के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण को अमल में लाने का मतलब आइसीडीएस या आंगनबाड़ी केंद्रों को खत्म करना नहीं है, परंतु उन पर व्यर्थ का बोझ कम करना है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि आइसीडीएस का फलक काफी व्यापक है और उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की आवश्यकता रहेगी ही, लेकिन जन-स्वास्थ्य और मां-बच्चे के सुपोषण के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण का निष्पक्ष पायलट परीक्षण किया जाना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में नीति और सेवा वितरण को दक्ष बनाने के लिए हमें आधुनिक तकनीक का लाभ उठाना ही होगा।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

संस्कृति के अजस्र प्रवाह का समय

नीरजा माधव

कार्तिक मास दीपोत्सव का संदेश लाने के साथ ही अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का आह्वान करता भी दिखता है

अपने आपको प्रकाश की अनंत धारा से जोड़े रखने के लिए आत्मिक शक्तियों के जागरण के लिए हर सांझ मिट्टी का एक दीप हर मन की आवश्यकता है। यह बताने के लिए भी कि अनंत प्रकाश की प्रतीक्षा में हम भी जाग रहे हैं। यह लौ ही जब पूर्णता को प्राप्त होती है तो परम प्रकाश बन जाती है। तुलसी चौरे के नीचे मिट्टी के दीये में टिमटिमाती लौ किस प्रकार अनंत प्रकाश की धारा बन जाती है। इस अनंत प्रकाश को देखने वाली आंखों को नींद से जगाने के लिए भी आता है यह दीप मास। आश्विन और कार्तिक मास जागरण का विशेष काल है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष पर हम अपने पितरों को कुश, जल और तिल समर्पित कर उनका आह्वान करते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सुख, समृद्धि, आरोग्यता और कृपा की कामना करते हैं।

इसी आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से सिगुणात्मिका प्रकृति रूपा मां लक्ष्मी, सरस्वती और काली को प्रसन्न करने का अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। शक्ति जागृत होती है और पूरी धरती शस्य श्यामला हो उठती है। धान की सोंधी बालियों में श्री और रिद्धि-सिद्धि का सौंदर्य कृषि प्रधान देश के हर आंगन, देहरी, द्वार पर बिखर जाता है। चिड़ियों का झुंड चहचहाने लगता है। बच्चों की किलकारियां और मेले-ठेले का आनंद सबकी रगों को पुलक से भर देता है। शरद पूर्णिमा पर कोजागरी उत्सव के बहाने स्वयं लक्ष्मी निकल पड़ती है अपने भक्तों के आनंद में शामिल होने। एक मां जो यह देखने पृथ्वी पर आती है कि कौन जाग रहा है? को जाग री! अर्थात जो जागेगा, सचेत रहेगा, वही वास्तविक आनंद का उपभोग कर पाएगा। यह जागना केवल आंखों का खुला रखना नहीं है, अपितु अंतर्मन के निकुंज को इस योग्य बनाना है कि सोलह कलाधारी लीला पुरुष श्रीकृष्ण के महारास की निशा का अनहद निनाद सुनाई पड़ सके। उनकी मुरली की टेर में परब्रह्म का वह प्रथम नाद हमारे भी कान सुन सकें। कोजागरी के साथ ही प्रारंभ हो जाता है दीपदान का सिलसिला। श्री, सरस्वती और महाकाली से

ऊर्जा प्राप्त करने का क्रम और इस प्रकार पूरा कार्तिक मास दीपोत्सव का मास बन जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का आह्वान बन जाता है। शायद इसीलिए कार्तिक को सबसे पुण्यदायी मास कहा जाता है।

राम की विजय के साथ उनके आगमन और राज्याभिषेक पर हजारों दीपों को प्रज्जवलित करने का सिलसिला, गोवर्धन पूजा से लेकर अन्नकूट और अक्षय नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे खीर के साथ अमृतपान करने और देवों की दीपावली से पूर्व ब्रह्मांड के पालनकर्ता श्री विष्णु के योगनिद्रा से उठने की महिमामंडित एकादशी के साथ ही तुलसी विवाह की परंपरा को फिर से जीने का क्रम। शक्ति के जागरण का ही काल नहीं है यह, अपितु शक्ति की अधिष्ठान हरिहर रूपी परब्रह्म के भी योगनिद्रा से जागरण का काल है यह। इस पूरे क्रम में गंगा और अन्य पवित्र नदियों की धारा हमारी संगिनी बनी रहती है, जीवन-धारा बनी रहती है। नदियों की धारा में हर सांझ एक दीप चलाने का क्रम भंग नहीं होता, तुलसी चौरे पर कच्ची मिट्टी के दीये में झिलमिलाती लौ का प्रवाह नहीं थमता। दीप से आलोकित प्रत्येक सांवली सांझ अपने आगे आने वाली सांझ की हथेली पर एक नन्हा दीप रखती है और आह्वान करती है अंधेरे को चुनौती देने, आक्रामक कीट-पतंगों जैसी दुष्प्रवृत्तियों के नाश का और इस प्रकार पूरे वर्ष के लिए सुख-शांति का मधु एकत्र करने का। निश्चय ही इस जुड़ाव में अनेक बाधक शक्तियां भी आती हैं। कार्तिक के अमावस की रात में महाकाल का आह्वान इसीलिए किया जाता है कि वे हमारे मार्ग में आने वाली इन राक्षसी प्रवृत्तियों का दमन कर प्रकाश से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करें। कभी रावण राक्षस था, महिषासुर जैसे दैत्यकुल थे जिनका संहार करने के लिए श्री विष्णु को रामावतार, कृष्णावतार या दुर्गारूप धारण करना पड़ा।

महाकाली, चण्डिका, मुंडमाला, आदि शक्तियों के रूप में आद्यशक्ति को इस राक्षसों के वध के लिए स्वयं अस्त्र-शस्त्र उठाने पड़े। आज उनकी शक्लें बस बदल गई हैं। आतंकी वेश में, भ्रष्टाचारी और दुराचारी वेश में, हम उन्हें प्रतिदिन देख रहे हैं। कोई अदृश्य शक्ति मानव वेशधर अपनी भुजाओं में महाकाली का तेज भर उन आतंकी तत्वों का नाश करने में लगी है। रक्तबीज की तरह पनप रहे इन आतंकी राक्षसों का समूल नाश होना समय के गर्भ में है पर हमें सजग हो शक्ति का आह्वान करना है, सीमा पर डटे अपने राम जैसे सैनिक भाइयों का मनोबल ऊंचा करना है। उनके लिए हमें शक्ति की आराधना करनी है, देवी जागरण करना है और दैत्य विनाशिनी महाकाली को प्रसन्न करना है। भारतीय संस्कृति का एक अजस्र प्रवाह, उससे फूटतीं अनंत परंपराएं। हम इस दीप शृंखला की एक नन्हीं लौ भी बन सकें तो धन्य हो जीवन।

response@jagran.com

ऊर्जा

दुख क्यों

मनुष्य इस भौतिक जगत में तमाम दुखों को अपने ऊपर ओढ़े हुए है। दुख तकलीफ से छूट जाने का प्रयास तो वह बहुत करता है, लेकिन जीवन में प्रविष्ट हो चुके दुख और तकलीफ आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। आज प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। उसकी स्वाभाविक मुस्कुराहट कहीं गुम हो गई है। हर चेहरा उदास, गमगीन और चिंतित दिखलाई पड़ता है। वह हंसने का प्रयास तो करता है, लेकिन अस्वाभाविक हंसी उसकी पोल खोल देती है। ये दुख मनुष्य के जीवन में क्यों हैं? क्यों नहीं इनसे पीछा छूट पाता? सर्वप्रथम दुखों के मूल कारण को जानना होगा तत्पश्चात उनसे छूटने के उपायों पर विचार करना होगा।

अविद्या से उत्पन्न अज्ञान ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। इसी अविद्या रूपी अंधकार के कारण हम बार-बार इस जगत रूपी दुखालय में आकर फंस जाते हैं। हमें सत्य दिखलाई नहीं पड़ता। इस दृश्यमान जगत को ही सत्य मानकर उसको पकड़ लेने की चेष्टा करना ही दुखों के भंवर जाल में फंसने का कारण बन जाता है। सांसारिक चकाचौंध और भौतिकता के इस साम्राज्य में अपने निज स्वरूप को मनुष्य भुला बैठा है। आज दृश्यमान भौतिक जगत रूपी छाया रूपी माया को पकड़ लेने की होड़ सी मच गई है। इसी का परिणाम हैं दुख और तकलीफ। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बाह्य चमक-दमक हमें इंद्रिय लोलुप बना रही है। आज ऐसी सोच स्थापित हो गई है कि किसी प्रकार से भी भौतिक साधन संपन्न बनकर इंद्रिय सुख का भरपूर भोग करने में सक्षम हो जाया जाए। इंद्रियों को किस प्रकार तृप्त किया जाय बस इसी को प्रधानता प्रदान कर दी गई है।

भौतिक संसाधनों से इंद्रिय सुख प्राप्त कर लेने की यह लालसा जीव को दुखों के जाल में धकेल देती है। अब दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस अविद्या रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान के प्रकाश में रास्ता ढूढ़ निकालना होगा। ज्ञान रूपी प्रकाश में हमें आगे बढ़ना होगा। सर्वप्रथम हमें मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त हुआ है इसकी सार्थकता पर विचार करना होगा। फिर यह विचार भी करना होगा कि यह प्राप्त मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है। इसलिए इस सतत परिवर्तनशील विनाशी जगत को पकड़ लेने की अभिलाषा का पूर्ण रूप से त्याग करना होगा।

अशोक वाजपेयी

तथ्य-कथ्य | हस्तशिल्प निर्यात (करोड़ रुपये में)

स्रोत : हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन समिति

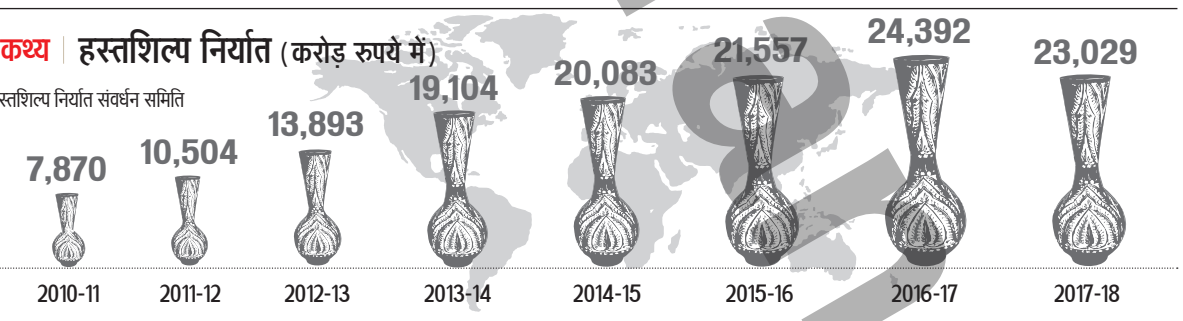

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

देशहित पर भारी निजी हित

राजनीति में सही-गलत का पैमाना शीर्षक से लिखे अपने लेख में सुरेंद्र किशोर ने देश की राजनीति में स्वार्थी लोगों का आना देशहित और जनहित के लिए अनुचित बताया है। देश की राजनीति में येन-केन-प्रकारेण अधिकाधिक धन कमाने कि परंपरा चल पड़ी है। देश की राजनीति में अगर स्वार्थ हावी नहीं होता तो आज देश विभिन्न समस्याओं के मकड़जाल में न उलझा होता। देश की राजनीति में जिस दिन परोपकारिता, देशहित और जनहित के बारे सोचने वाले लोग आना शुरू हो जाएंगे, उस दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की काया ही पलट जाएगी और देश की राजनीति के अच्छे दिन आ जाएंगे। देश की राजनीति में स्वच्छ अभियान देश का मतदाता जागरूक होकर चला सकता है।

raju09023693142@yahoo.com

राम मंदिर पर राजनीति

अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिए राज्यसभा में भाजपा के सदस्य राकेश सिन्हा ने शीतकालीन सत्र में निजी बिल लाने को कहा है। लेकिन इस बिल को पास कराना आसान नहीं होगा। क्योंकि विपक्षी दल ऐसा नहीं होने देंगे। वैसे भी मंदिर बनाने के प्रति कोई गंभीर नहीं है। सभी दल इसको लेकर केवल राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि अगर राममंदिर का निर्माण हो गया तो सभी दलों की वोट की राजनीति खत्म हो जाएगी। इस मामले में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्रीराम किसी एक दल के आराध्य नहीं हैं वे सबके भगवान हैं और इसी कारण सभी दलों को मिलकर इस समस्या का हल खोजना चाहिए।

नीरज कुमार पाठक, भवन

पटाखों पर पूर्ण रोक लगे

दिवाली प्रकाश और स्वच्छता का पर्व है जिसे इसकी मूल भावना और अर्थ में ही मनाना सही और सर्वहित में है। खुशी की बात है कि पिछले कई वर्षों से जानलेवा प्रदूषण से बचने के लिए देश की प्रबुद्ध जनता भी अब आतिशबाजी से दूर हो रही है। यह एक अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट भी इस दिशा में ऐतिहासिक निर्देश दे रहा है। पटाखों पर छूट नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो पटाखे जीवन के लिए खतरा बन रहे हैं, उनका इस्तेमाल बंद ही होना चाहिए।

वेद मामूरपुर ,नरेला

कम चलें पटाखे

बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों का उपयोग कम से कम किया चाहिए। यह वक्त का तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। यह हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए जरूरी है। पटाखों से धन का अपव्यय होता है, साथ ही साथ आगजनी और जान माल की भी हानि होती है। ऐसे में देश के प्रत्येक नागरिक को समझदारी परिचय देना चाहिए।

hemahariupadhyay@gmail.com

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

भारत की एकता के प्रतीक सरदार पटेल का जन्मदिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। इस शुभ अवसर पर उनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने पूरे गर्मजोशी से करते हुए भारत को नई सौगात भेंट की। इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है,जो उनके विलक्षण व्यक्तित्व,ऊंचे विचार, साहस, दृढ़ निश्चय तथा एकता का प्रतीक है। उनकी यह प्रतिमा भारत को वैश्विक पटल पर विशेष पहचान भी दिलाएगी।

सौरभ पाठक, ग्रेटर नोएडा

विश्व बैंक की मुहर

विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस 2019 की रिपोर्ट में दुनिया के 190 देशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग सूची में भारत 23 वें पायदान का सुधार करते हुए 100वें से 77 वें स्थान पर आ गया है। यह रिपोर्ट निश्चित रूप से वर्तमान केंद्र सरकार के लिए बेहद उत्साहवर्धक है। क्योंकि 2014 में सरकार बनते ही प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि हमारी सरकार इस लिस्ट में 142वें स्थान से टॉप 50 में आने का लक्ष्य निर्धारित करती है। सरकार को पहले 2 वर्षों में कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन पिछले 2 वर्षों में इस क्षेत्र में शानदार सफलता हासिल करते हुए टॉप 80 देशों की सूची में जगह बना पाने में सरकार कामयाब हुई है। यह सफलता 2019 में होने वाले आम चुनाव के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। कारोबारी माहौल की सुगमता को जांचने के लिए विश्व बैंक ने 10 मापदंड निर्धारित किए हैं, जिसमें भारत ने 6 मापदंडों में सुधार किया है। विश्व बैंक ने नोटबंदी और जीएसटी जैसे साहसिक कदमों की सराहना की है, लेकिन कर भुगतान के स्तर पर भारत दो स्थान फिसल गया है। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के लिए कुछ महत्वपूर्ण सलाह भी दी गई है, जिसमें रियल स्टेट पंजीकरण, कारोबार शुरू करने और अनुबंध के प्रवर्तन में लगने वाला समय यदि कम कर दिया जाए तो भारत टॉप 50 में भी शामिल हो सकता है। कारोबारी माहौल को तेजी से सुधारने की दृष्टि से भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है। इस तरह वर्तमान केंद्र सरकार कारोबार सुगमता के लिए जो प्रयास कर रही है उस पर विश्व बैंक ने भी अपनी मुहर लगा दी है। तमाम तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि केंद्र सरकार कारोबार के क्षेत्र में अपने द्वारा किए गए प्रयास में सफल होती दिख रही है।

sumitkumarjha910@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

पाकिस्तान के इस्लामवादियों ने ईशनिंदा की आरोपी आसिया बीबी को रिहा करने वाले जजों की हत्या करने की धमकी दी है। उनके भय से आसिया के वकील भी कहीं छिप गए हैं। अपनी जान बचाने के लिए आसिया भी पाकिस्तान छोड़ सकती हैं। कैसा देश है वह?

तसलीमा नसरीन@taslimanasreen

हे भगवान! ये क्या हो रहा है बिहार में? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीट शेयरिंग में व्यस्त हैं और पुलिस अब अपराधियों को पकड़ने के बजाय आपस में ही झगड़ रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही कहा है, 'बिहार के हालात भयावह और डरवाने हैं।'

तेजस्वी यादव@yadavtejashwi

चारों ओर से घिरी और घबराई बीजेपी अब अपना ब्रह्मास्त्र निकाल रही है। आने वाले कुछ महीनों में या तो जवान और किसान होगा, नहीं तो हिंदू और मुसलमान होगा।

योगेंद्र यादव@_YogendraYadav

भारत में विनिर्माण कार्यों में एमएसएमई सेक्टर अकेले 45 प्रतिशत योगदान करता है। ऋण की सुविधा इस सेक्टर की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। एमएसएमई हब इस सेक्टर के विकास और इनके वैश्विक उद्यम बनने में सहायक होगा।

अरविंद गुप्ता@buzzindelhi

जनपथ

आंखें जलतीं दिल जले हुआ फेफड़ा जाम,
धुआं-धुआं हर ओर है हर दिन सुबहोशाम।
हर दिन सुबहोशाम नर्क बन बैठी दिल्ली,
पूरी दुनिया आज उड़ाती इसकी खिल्ली।
आने वाली नस्ल भला किसका मुंह ताकें,
यदि अब भी हम लोग मूंदकर बैठे आंखें।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन.संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधी